फरवरी, 2022 वर्ष : 43 अंक : 02

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

तिब्बती मुद्दे के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक

मूल्य :10 रु , वार्षिक : 100 रु

फरवरी, 2022 वर्ष : 43 अंक :02

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित

तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

कलोन नोरजीन डोलमा के साथ विशेष समन्वयक अज़रा ज़ेया

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी , जिगमे सुलट्रिम

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन पलजोर , तेनजिन जोरदेन

वितरण प्रबंधक
छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

उम्मीद है कि यूक्रेन में बातचीत से शांति बहाल होगी 1

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने यूक्रेन के साथ एकजुटता जताई, समाधान के रूप में हिंसा उपयोग करने की निंदा की 2

अवैध रूप से बंदी बनाए गए बीमार तिब्बती विद्वान के साथ दुर्व्यवहार जानलेवा हो सकता है 3

मोबाइल फोन निरीक्षण के बाद ड्रागो में ओर तिब्बती गिरफ्तार 4

पूर्व तिब्बती राजनीतिक बंदी नवांग ग्यालत्सेन का ५८ वर्ष की उम्र में निधन 5

कालोन नोरज़िन डोल्मा और सचिव कर्मा छोयिंग वाशिंगटन ने तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक अज़रा ज़ेया के साथ मुलाकात की 6

भारतीय सांसद ने भारत सरकार से तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने का आग्रह किया 7

स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बीजिंग ओलंपिक पर सुनवाई के दौरान चीन द्वारा मानवाधिकारों की हनन पर बयान दी 8

जापानी भिक्षुओं ने तिब्बत में बुद्ध प्रतिमा विध्वंस करने पर चीनी शासन की निंदा की 9

तिब्बत पर जर्मन संसदीय समूह ने नए विधायी कार्यकाल के दौरान पहली बैठक बुलाई 10

यूएनपीओ महासचिव ने तिब्बत कार्यालय का दौरा किया 11

वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंध समिति के अधिकारियों से मुलाकात की 12

समाचार -

प्रतिनिधि नामग्याल छोहडुप ने अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत रशद हुसैन से मुलाकात की 13

ओओटी दक्षिण अफ्रीका ने 'तिब्बत क्यों मायने रखता है' शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन किया 14

स्विस-तिब्बती समुदाय ने तिब्बत पर चीन के निरंतर कब्जे के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया 15

सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसंग फेंडे और तेनजिन जिग्दल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की 16

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया ने तिब्बत पर अपने काम को फिर से संगठित करने के लिए वर्चुअल बैठक आयोजित की 17

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया के असम के क्षेत्रीय संयोजक ने स्वर्गीय श्री नरेन चंद्र दास को श्रद्धांजलि दी 18

फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम और अन्य तिब्बत समर्थक समूहों ने गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठक की 19

शिलांग कल्याण अधिकारी पेमा धोंडुप ने राजभवन में मेघालय के राज्यपाल से मुलाकात की 20

श्री त्सेरिंग येशी द्वारा तिब्बत के लिए 'राइड फॉर प्राइड' बाइक अभियान का दिल्ली में समापन 21

एसएफएफ के शहीद डिप्टी लीडर तेनज़िन नोरबू भारत में वीरता सेवा के लिए सम्मानित 22

मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com

बुद्ध प्रतिमा का विध्वंसः कैसे शी जिनपिंग तिब्बत में पारंपरिक बौद्ध धर्म को नष्ट कर रहे हैं 23

तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी में जन आंदोलन 24

अपनी बात

तिब्बती संघर्ष को अमरीका सरकार का समर्थन जारी

निर्वासित तिब्बत सरकार, जो कि तिब्बतियों की लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली से निर्वाचित सरकार है, के नये मंत्री (कालोन) नॉर्जिन डोल्मा द्वारा तिब्बतन एडवोकेसी कैम्पेन में अपनी अमरीका यात्रा के दौरान चीन सरकार के साथ वार्ता पुनः प्रारंभ किये जाने पर जोर स्वागतयोग्य है। इसी फरवरी, २०२२ को अपनी सप्ताहभर की इस यात्रा में उन्होंने अमरीकी राज्य विभाग के अधिकारियों से भेंट की। वे तिब्बत संबंधी मामलों के समन्वयक अजरा से और अन्तरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के नये राजदूत राशद हुसैन से मिले। उन्होंने विभिन्न अमरीकी अधिकारियों के साथ तिब्बती शरणार्थियों, तिब्बतियों के पलायन एवं पर्यावरण आदि विषयों पर चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि चीन की दमनकारी नीति के कारण तिब्बती ही तिब्बत में अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं। चीन द्वारा तिब्बती लोगों पर बढ़ते अत्याचार के कारण कई तिब्बती अपने हाथों अपने ही शरीर में आग लगाकर आत्मदा करने को बाध्य हैं। उनका यह बलिदान किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित करने के लिये काफी है लेकिन चीनी प्रशासन अत्यन्त संवेदन शून्य है। वह आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों के परिजनों को प्रताड़ित और दण्डित करने में लगा है। नॉर्जिन डोल्मा ने यह भी बताया कि तिब्बत के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को चीन सरकार षड्यंत्रपूर्वक एवं सुनियोजित तरीके से नष्ट कर रही है।

अमरीका सरकार के विभिन्न अधिकारियों को कालोन नॉर्जिन डोल्मा ने तिब्बतियों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में प्रामाणिक जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि परमपावन दलाईलामा की प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद से निर्वासित तिब्बत सरकार का तिब्बती समुदाय द्वारा निर्वाचन किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण-संवर्धन में महत्वपूर्ण कदम है। उनका स्पष्ट मत था कि चीन सरकार एवं निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता पुनः प्रारंभ होनी चाहिए। इस वार्ता का आधार "मध्यममार्ग" हो। मध्यममार्ग चीन के संविधान और राष्ट्रीय कानून के अनुकूल है।

चीन सरकार प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामले अपने पास रखे तथा अन्य सभी विषयों, जैसे - कृषि, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, उद्योग आदि पर कानून बनाने का अधिकार तिब्बतियों को सौंपे। इससे चीन की एकता-अखंडता-संप्रभुता की सुरक्षा के साथ ही तिब्बतियों को स्वशासन का अधिकार मिल जायेगा। यही है तिब्बत को "वास्तविक स्वायत्तता"। अभी चीन ने तिब्बत को तथाकथित स्वायत्तता दे रखी है। उसने तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों को चीनी भूभाग में मिला लिया है।

तिब्बत अवैध चीनी आधिपत्य के पूर्व भारत एवं चीन के बीच स्थित एक स्वतंत्र देश था। उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की जाये। तिब्बतियों एवं तिब्बत समर्थकों के पक्ष में बढ़ते अमरीकी सरकार के सहयोग और समर्थन की उपेक्षा चीन के लिये नुकसानदेह साबित होगी। विश्वजनमत तिब्बती मध्यममार्ग नीति के पक्ष में है। तिब्बती पूर्ण स्वतत्रंता की मांग छोड़कर सिर्फ वास्तविक स्वायत्तता मांग रहे हैं। तिब्बत समस्या का व्यावहारिक समाधान यही है। तिब्बत एवं चीन के साथ संपूर्ण विश्व का इससे कल्याण होगा।

भारत में रह रहे सभी ४० तिब्बती सांसदों द्वारा तिब्बती कॉलोनियों की वार्षिक यात्रा भी स्वागतयोग्य है। इसी फरवरी माह में तिब्बती कॉलोनियों की समस्याओं को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा -जाना। उन्होंने स्थानीय भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों, जैसे - कलक्टर, एस.पी. आदि से भेंट कर उनकी मदद प्राप्त की। वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सांसद जयराम रमेश, शशि ठरूर तथा तिब्बत समर्थक सर्वदलीय संसदीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुजीत कुमार से मिले। सांसदों की रिपोर्ट पर तिब्बत सरकार की कार्यकारिणी विचार करती है। सांसदों के इस कदम से तिब्बतियों एवं भारतीयों के विश्वासपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण संबंध और भी मजबूत होते हैं। इससे तिब्बतियों के साथ भारतीयों को भी तिब्बती नीति एवं कार्यक्रमों का पता चलता है। इस दृष्टि से तिब्बती सांसदों का यह वार्षिक कार्यक्रम सराहनीय है। इससे तिब्बती कॉलोनियों में स्थानीय भारतीय लोगों एवं प्रशासन का सहयोग लगातार बढ़ता रहेगा। तिब्बतियों एवं भारतीयों के बीच तिब्बत संबंधी नवीनतम जानकारियों से भरपूर प्रामाणिक जागरुकता लाने का यह प्रभावी साधन है।

जागरुकता प्रयासों का ही परिणाम है कि चीन में ४ फरवरी, २०२२ से आयोजित विंटर ओलंपिक के बहिष्कार हेतु सार्थक विरोध आंदोलन विश्वस्तर पर हुए। ओलंपिक कार्यालय के सामने सत्याग्रह तथा भारत में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन इसी विरोध के उद्धरण हैं। चीन सरकार की धमकियों के बावजूद अनेक देशों ने इस आयोजन का राजनयिक बहिष्कार किया। इससे चीन सरकार की तिलमिलाहट के साथ तिब्बत में जारी उसकी क्रूरतापूर्ण अमानवीय नीति भी स्पष्ट हो गई । अमरीका आदि अनेक देशों ने साबित कर दिया कि चीन की तिब्बत नीति का वे जोरदार विरोध जारी रखेंगे।

विंटर ओलंपिक के आयोजन से चीन अपनी छवि चमकाने में लगा था। उसे विश्वास था कि विश्वजनमत तिब्बत में चीनी अत्याचार को भूला देगा। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। साथ ही विश्वजनमत कोरोना महामारी के लिये भी चीन को जिम्मेदार समझता है। कोरोना महामारी चीन के वुहान से पूरे संसार में फैल गई। ऐसे समय भी चीन सरकार निम्न दर्जे के चिकित्सीय उपकरण तथा दवाई आदि बेचकर "अशुभलाभ" कमा रही थी। उसका यह कार्य मानवता के विरुद्ध था। कोरोना महामारी फैलाकर उसने फिर से साबित कर दिया कि दया, करुणा, प्रेम, शांति आदि मानवीय मूल्य उसके लिये महत्वहीन हैं

प्रो. श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (राजस्थान)
मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◇ उम्मीद है कि यूक्रेन में बातचीत से शांति बहाल होगी

dalailama.com, २८ फरवरी २०२२

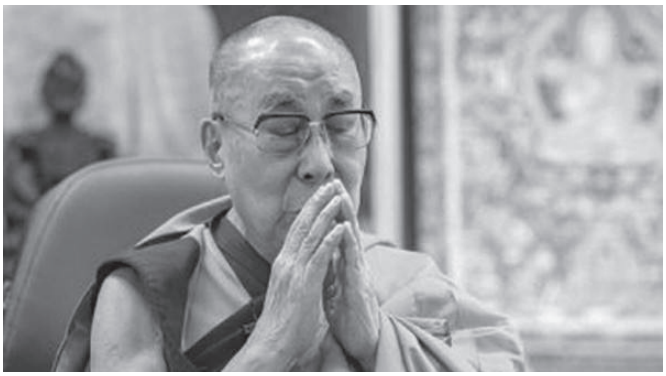

परम पावन दलाई लामा

यूक्रेन में संघर्ष से मुझे गहरा दुख हुआ है। आज हमारा विश्व एक -दूसरे पर इतना अन्योन्याश्रित हो गया है कि दो देशों के बीच हिंसक संघर्ष निश्चित तौर पर शेष विश्व को प्रभावित करता है। युद्ध पुराना तरीका हो चुका है- अब अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। हमें सभी लोगों को भाई-बहन मानकर मानवता की एकता की भावना विकसित करने की आवश्यकता है। इस तरह हम एक अधिक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करेंगे।

बातचीत के माध्यम से समस्याओं और असहमति को अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। वास्तविक शांति आपसी समझ और एक-दूसरे की भलाई करने से आती है।

हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। २०वीं सदी युद्ध और रक्तपात की सदी थी। २१वीं सदी संवाद की सदी होनी चाहिए।

मैं प्रार्थना करता हूं कि यूक्रेन में तेजी से शांति बहाल हो।

◇ सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने यूक्रेन के साथ एकजुटता जताई, समाधान के रूप में हिंसा उपयोग करने की निंदा की

tibet.net, २८ फरवरी२०२२

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने हाल ही में अपने एक संदेश में यूक्रेन संकट के साथ एकजुटता प्रकट की।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेंपा छेरिंग

सिक्योंग ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि आज की दुनिया में हिंसा को 'अमानवीय' और 'अनैतिक' बताते हुए निंदा की और यूक्रेन में शांति बहाल करने का आह्वान किया।

सिक्योंग ने ट्वीट किया, 'जैसा कि तिब्बती कहावत है- बड़े कीड़े छोटे को खा जाते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण हमें १९५० में तिब्बत पर आक्रमण की याद दिलाता है। हिंसा का सहारा लेना अमानवीय है और आज की दुनिया में अप्रचलित है। यूक्रेन में शांति बहाल होनी चाहिए।'

◇ अवैध रूप से बंदी बनाए गए बीमार तिब्बती विद्वान के साथ दुर्व्यवहार जानलेवा हो सकता है

tibet.net, १४ फरवरी२०२२

तिब्बती लेखक और विद्वान गो शेरब ग्यात्सो

एक विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी के अनुसार, १० साल की सजा काट रहे प्रख्यात तिब्बती विद्वान गो शेरब ग्यात्सो इस समय गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। अक्तूबर- २०२० में गिरफ्तारी के बाद से जेल में उन्हें कई बार मारा-पीटा गया और उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया गया। उनके बीमार होने का यह प्रमुख कारण है।

जेल में भोजन और चिकित्सा उपचार जैसी उचित जरूरी सुविधाओं की कमी के साथ-साथ मारपीट किए जाने के कारण शेरब का स्वास्थ्य और भी खराब हो गया है। गो शेरब कथित तौर पर फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं। माना जाता है कि १९९८ में पहली बार जेल में डाले जाने के समय ही उन्हें यह बीमारी लग गई थी, तब से ही वह नियमित तौर पर दवाओं पर चल रहे हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में उनकी बीमारी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है और चीनी सरकार द्वारा कैद तिब्बती भिक्षु की 'तत्काल और बिना शर्त' रिहाई की मांग की गई है। रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच के चीन मामलों की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने कहा कि, 'एक बार फिर चीनी सरकार द्वारा एक तिब्बती को गलत तरीके से कारावास की सजा दी गई है, जिससे उनकी मौत होने का खतरा उपस्थित हो गया है।' उन्होंने कहा, 'गो शेरब ग्यात्सो को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उनकी गहन चिकित्सा देखभाल दी जानी चाहिए।'

शेरब के मामले के आलोक में कहा जा सकता है कि कैदी में दुर्व्यवहार और उचित चिकित्सा देखभाल न किए जाने के कारण ही चीनी पुलिस की हिरासत में लंबे समय से सजा काट रहे कई तिब्बती कैदियों की मृत्यु हुई है।

चीनी अधिकारियों ने गो शेराब को २६ अक्टूबर २०२० को उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह अपने इलाज के लिए चेंगदू में थे। हालांकि गो शेरब

ग्यात्सो को लंबी जेल की सजा देने के औचित्य में ठोस और वैध सबूतों का अभाव था। चीनी अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप तिब्बती स्वतंत्रता के समर्थन का संकेत देते हैं। एक अन्य स्रोत ने उनकी सजा के लिए मुख्य आधार उनकी पुस्तक रुप में रिकॉर्ड की गई बातचीत का संग्रह- फाइंड योर ओन पाथ' की सामग्री को बताया गया है। लेकिन उनके ऊपर लगाए जा रहे इन आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे। वह वर्तमान में चुशुल जेल (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में जेल नंबर- १) में बंद हैं।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के एक समूह ने संयुक्त रुप से बयान जारी कर २१ जुलाई २०२१ को गो शेरब ग्यात्सो के गायब होने पर चीनी सरकार से सवाल पूछे थे और इसको लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। चीनी सरकार ने २७ अगस्त २०२१ को दिए अपने जवाब में कहा कि गो शेरब ग्यात्सो को 'अलगाव को उकसाने' के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, यह पता चला कि ल्हासा सिटी इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने अभी तक उनके मामले पर फैसला सुनाया नहीं था। तिब्बती सूत्रों ने बाद में बताया कि उन्हें १० साल की सजा दी गई थी।

तिब्बती पहचान को बनाए रखने के लिए एक प्रतिष्ठित और अत्यधिक मुखर तिब्बती सेनानी के रुप में गो शेरब ग्यात्सो कोई नया नाम नहीं है। वह चीनी अधिकारियों के साथ संघर्ष और मतभेद रखने वाले प्रमुख कार्यकर्ता के रुप में पहचाने जाते हैं। चेंगदू में गिरफ्तारी से पहले गो शेरब ग्यात्सो को पहले १९९८ से २०११ के बीच तिब्बत और तिब्बती लोगों को कमजोर करने वाली चीनी नीतियों की आलोचना करने वाले उनके लेखन के लिए कई बार हिरासत में लिया गया था।

◇ मोबाइल फोन निरीक्षण के बाद ड्रागो में ओर तिब्बती गिरफ्तार

tibet.net, १४ फरवरी२०२२

ड्रागो मठ

एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने मोबाइल फोन में 'राजनीतिक रुप से संवेदनशील जानकारी' रखने के कारण इस साल जनवरी में ड्रागो में तीन तिब्बती तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार किया गया। चीनी अधिकारियों ने इन तीर्थयात्रियों के मोबाइल फोन की जांच के आधार पर यह कार्रवाई की। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि हाल ही में ड्रागो मठ में ३० फुट ऊंची मैत्रेय प्रतिमा को तोड़े जाने की तस्वीरें और वीडियो इन तिब्बतियों द्वारा अपने मोबाइल फोन में रखने का मामला सामने आया है।

रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीनों तिब्बती तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ड्क्यब काउंटी, चामडो (चीनीः चांगदू) के निवासी हैं और सेर्थर काउंटी के लारुंग गार में मठवासी समुदाय के दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। बताया गया कि निरीक्षण के दौरान कुछ तस्वीरें उनके वीचैट खातों की पृष्ठभूमि में लगी पाई गईं। उन्हें फिलहाल चमडो थाने में रखा गया है।

एक अन्य पुष्ट घटना में इससे पहले ड्रागो मठ के एक भिक्षु ताशी दोरजे को ०१ या ०२ जनवरी २०२२ के आसपास गिरफ्तार किया गया था। उन पर तिब्बत के बाहर हाल ही में ड्रागो अशांति के बारे में जानकारी भेजने का आरोप लगाया गया था।

एक स्रोत ने बताया कि ड्रागो काउंटी में उच्च स्तर की सेंसरशिप लगी हुई है। यहां बुद्ध प्रतिमाओं के विध्वंस के फ़ोटो और वीडियो को रखना या साझा करना और फ़ोटो (बुद्ध प्रतिमा) को वीचैट पर पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) फ़ोटो के रुप में उपयोग करने को राजनीतिक रुप से संवेदनशील माना जाता है और इस आरोप में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाता है।'

ड्रागो में हालिया अशांति पिछले अक्टूबर में उस समय शुरु हुई थी जब चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बती पहचान पर जानबूझकर और अथक हमले की शृंखला में एक तिब्बती मठवासी स्कूल को जबरन ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद दिसंबर में अधिकारियों ने दो विशाल बुद्ध मूर्तियों, स्थानीय निवासियों द्वारा अत्यधिक सम्मानित, 45 विशाल प्रार्थना-चक्रों और प्रार्थना झंडे को जलाने की शुरुआत की। विध्वंस के इन मामलों को उजागर करने के तिब्बतियों द्वारा किए गए हर प्रयास को बर्बरता से दबा दिया गया। परिणामस्वरूप, लगभग एक दर्जन तिब्बतियों को पकड़ लिया गया और उन्हें 'राजनीतिक पुनर्शिक्षा' पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए भेज दिया गया।

अपने शासन के प्रति तिब्बती समुदाय का सम्मान और उनकी स्वीकृति अर्जित करने के चीन के हर प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं। इस संबंध में हाल में की गई कार्रवाई के दौरान इसका विरोध करनेवाले तिब्बतियों के गिरफ्तार होने की अधिक खबरें सामने आ रही हैं।

◇ पूर्व तिब्बती राजनीतिक बंदी नवांग ग्यालत्सेन का ५८ वर्ष की उम्र में निधन

tibet.net, २३ फरवरी २०२२

तिब्बती राजनीतिक बंदी नवांग ग्यालछेन

हमारे स्रोत के अनुसार, तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए चीनी जेलों में 17 साल से अधिक समय गुजारने वाले एक पूर्व तिब्बती राजनीतिक बंदी का २२ फरवरी, २०२२ को निधन हो गया।

जानकारी के अनुसार, खराब स्वास्थ्य के कारण न्गोडुप ग्यालत्सेन के नाम से भी ख्यात न्वांग ग्यालत्सेन का निधन स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग ५:२२ बजे ल्हासा अस्पताल में हो गया। वह केवल ५८ वर्ष के थे।

न्वांग ग्यालत्सेन उन २१ डेपुंग भिक्षुओं में से एक थे, जिन्होंने २७ सितंबर १९८७ को ल्हासा में पहला महत्वपूर्ण स्वतंत्रता-समर्थक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ल्हासा के एक हिरासत केंद्र में चार महीने के लिए रखा गया था।

अपनी रिहाई के बाद भी उन्होंने तिब्बत की स्वतंत्रता और तिब्बती लोगों के मौलिक मानवाधिकारों के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने नौ अन्य भिक्षुओं के साथ अहिंसक राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए 'ग्रुप ऑफ टेन' का गठन किया।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्रुप- २२ की रिपोर्ट के अनुसार, इन 'दस भिक्षुओं' की अहिंसक राजनीतिक गतिविधियों में नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉकों पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रतियां मुद्रित करने का काम भी शामिल था। उन्होंने दलाई लामा द्वारा निर्वासन में तैयार किए गए १९६३ के संविधान के आधार पर भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए एक दस्तावेज भी छापा, जिसमें चीनी कब्जे से मुक्त एक लोकतांत्रिक तिब्बत की अवधारणा का प्रस्ताव रखा गया है।

अधिकारियों ने १३ मई १९८९ को इन दस भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया। २८ नवंबर १९८९ को ल्हासा पीपुल्स इंटरमीडिएट कोर्ट ने लगभग १५०० लोगों की उपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाया, जहां उन्हें प्रति-क्रांतिकारी समूहों में भाग लेने, अलगाववाद को भड़काने, जासूसी कृत्यों का संचालन करने और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को अवैध रूप से पार करने के आरोप में १७-१७ साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें उनकी लंबी सजा अवधि के अलावा पांच साल तक सभी राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का फैसला भी सुनाया गया।

'फ्री तिब्बत' की एक रिपोर्ट के अनुसार, नवांग को फिर से गिरफ्तार किया गया और बाद में २४ फरवरी २०१५ को अज्ञात आरोपों में नागचू के सोग काउंटी में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। संदेह जताया गया कि उन्हें 'देशभक्ति की शिक्षा' पर चीनी अधिकारियों के साथ टकराव के कारण उन्हें अपने मठ से बेदखल कर दिया गया था। उन्हें तीन सजा की सजा देकर ल्हासा की द्रापची जेल में रखा गया। सजा पूरी होने के बाद उन्हें ०७ मार्च २०१९ को रिहा कर दिया गया।

नवांग ग्यालत्सेन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ल्हासा शहर में तोएलुंगदेचेन (चीनी : दुइलोंगदेकिंन) काउंटी के रहने वाले हैं। वह १९८४ में डेपुंग मठ में भिक्षु बने।

◇ कालोन नोरज़िन डोल्मा और सचिव कर्मा छोयिंग वाशिंगटन ने तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक अज़रा ज़ेया के साथ मुलाकात की

tibet.net, २६ फरवरी२०२२

कालोन नोरजीन डोलमा तथा विशेष समन्वयक अज़रा ज़ेया के साथ सचिव कर्मा छुयिंग, प्रतिनिधि नामग्याल छोहडुप और अधिकारी ताशी दोंडुप

वाशिंगटन डी.सी.। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (डीआईआईआर) विभाग के कालोन नोरज़िन डोल्मा और सचिव कर्मा छोयिंग ने अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी. का एक सप्ताह के लिए अधिकारिक यात्रा किया था।

कालोन नोरज़िन डोल्मा ने २४ फरवरी २०२२ को तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक व विदेश मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार विभाग की अवर सचिव अज़रा ज़ेया के साथ मुलाकात की।

राज्य विभाग में कालोन नोरज़िन डोल्मा ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी एंबेसेडर-एट-लार्ज राशद हुसैन, विदेश विभाग के जनसंख्या, शरणार्थी और प्रवास के लिए उप-सहायक नैन्सी इज़ो जैक्सन और विदेश विभाग में लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम (डीआरएल) मामलों के उप-सहायक स्कॉट बुस्बी से भी मुलाकात की। इस अवसर पर डीआईआईआर सचिव कर्मा छोयिंग, तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्याल छोहडुप तथा सचिव ताशी धोंडुप भी उपस्थित थे।

१० नवंबर २०२१ को शपथ लेने के बाद कलोन की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है और विदेश उपमंत्री ज़ेया के साथ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की नेता की पहली व्यक्तिगत बैठक है। कलोन ने परम पावन दलाई लामा और सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग की ओर से उपमंत्री को बधाई दी। कलोन ने वर्तमान सीटीए प्रशासन की मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और तिब्बत मुद्दे को हल करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। यह यात्रा तिब्बत मुद्दे को हल करने में अमेरिकी प्रशासन और सीटीए के बीच भविष्य की रणनीति की रूपरेखा की नींव रखने के लिए है।

कलोन ने उन्हें समय और समर्थन देने के लिए धन्यवाद और आने वाले समय में उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की।
विशेष समन्वयक ज़ेया ने नोरज़ीन डोल्मा को कालोन नियुक्ति के लिए बधाई दी। उन्होंने आने वाले महीनों में परम पावन दलाई लामा और सीटीए अधिकारियों से मिलने के लिए धर्मशाला जाने की उत्सुकता व्यक्त की।

अवर सचिव अज़रा ज़ेया ने तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक नियुक्ति के बाद २२ दिसंबर २०२१ को उत्तरी अमेरिका में परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि नामग्याल छोहडुप के साथ अपनी पहली आधिकारिक बैठक की थी।

◇ भारतीय सांसद ने भारत सरकार से तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने का आग्रह किया

tibet.net, ४ फरवरी २०२२

राज्य सभा सांसद अमरेन्द्र धारी सिंह

दिल्ली। भारत की संसद के उच्च सदन राज्य सभा के सदस्य श्री अमरेंद्र धारी सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण में ३ फरवरी को तिब्बत का मुद्दा उठाया। श्री ए. डी. सिंह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए।

अपने भाषण में उन्होंने कहाः भारत को अपने दोस्तों के साथ खड़ा होना सीखना होगा। यदि नहीं तो हम एक बार फिर तिब्बत के अपने मित्रवत लोगों को नीचा दिखाने की ऐतिहासिक भूल को दोहरा रहे होंगे। यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि तिब्बतियों ने कभी भी चीनियों की संप्रभुता और आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया।'

'यहां तक कि तत्कालीन सरकार के बहुत ही आदरणीय नेता नेहरू ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने की सलाह दी और १९४९ में तिब्बत में सामरिक सैन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक युवा सैन्य अधिकारी जोरावर बख्शी को भेजा। चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं और बाकी इतिहास है। हालांकि, इस तेजी से बढ़ती बहुध्रुवीय दुनिया में राष्ट्र को कार्रवाई और निष्क्रियता दोनों के दीर्घकालिक परिणामों का सामना करना पड़ता है और भारत को अपने पड़ोस और उसके बाहर अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित के साथ खुद को संयोजित करना होगा।

◇ स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बीजिंग ओलंपिक पर सुनवाई के दौरान चीन द्वारा मानवाधिकारों की हनन पर बयान दी

tibet.net, ०४ फरवरी २०२२

धर्मशाला। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, भारत और कई अन्य देशों द्वारा ताबड़तोड़ बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार के बीच 'द कांग्रेसनल एक्सक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना (चीन पर कांग्रेस-कार्यकारी आयोग)' ने खेलों के उद्घाटन से एक दिन पहले गुरुवार ०३ फरवरी को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक मामले की सुनवाई आयोजित की। इस दौरान सीईसीसी के समक्ष गवाही देते हुए अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन- हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि चीनी सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के अनेक प्रकार से उल्लंघनों पर प्रकाश डालें, फिर भी अमेरिकी एथलीटों को 'क्रूर चीन' को नाराज करने के जोखिम से बचने की सलाह दी गई है।

अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी

स्पीकर पेलोसी ने कहा, 'हालांकि हम अपने एथलीटों का पूरा समर्थन करते हैं और उनके पीछे खड़े हैं, फिर भी हम चीन में मानवाधिकारों पर चुप नहीं रह सकते हैं और न ही चुप रहेंगे।' उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय चीन के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और उग्यूरों, तिब्बतियों और हांगकांग के लोगों के नरसंहार की सच्चाई से वाकिफ हैं, फिर भी चीन अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड की सच्चाई को छिपाने के लिए बार-बार प्रयास कर रहा है।

'कांग्रेस में कई लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ी है कि दुनिया पीआरसी के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सच्चाई को याद रखे और उन्हें जवाबदेह ठहराए जिसमें उन्हें ओलंपिक की मेजबानी के सम्मान से वंचित करने की मांग करना शामिल है।'

'अब कॉरपोरेट प्रायोजकों द्वारा सहायता प्राप्त आईओसी ने एक बार फिर २०२२ शीतकालीन ओलंपिक के लिए आंखें मूंद ली हैं।'

स्पीकर पेलोसी ने कहा, 'अगर हम व्यावसायिक हितों के कारण चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो हम कहीं भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार खो देंगे।'

अब जबकि खेल आयोजित हो ही रहे हैं, अमेरिकी कांग्रेस अपने ही शासन के तहत पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चीन के खिलाफ साहसिक कार्रवाई करने की संस्तुति करती है।'

पिछले साल दिसंबर में 'उग्यूर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम' पारित करने के बाद अमेरिका एक बार फिर चीन के साथ अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक और अधिनियम को पारित करने की तैयारी कर रहा है। चीन को पछाड़ने के लिए २०२२ का अमेरिका प्रतियोगिता अधिनियम (द अमेरिका कंपिटेस ऐक्ट ऑफ २०२२) दुनिया भर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए नए अवसर प्रदान करके देश की अर्थव्यवस्था के नवाचार इंजन को फिर से मजबूत करने का प्रस्ताव करता है।

स्पीकर पेलोसी ने अपने संबोधन को समाप्त करते हुए कहा, 'पीआरसी के शासन में पीड़ित सभी लोगों को अमेरिका देख रहा है, अमेरिका उनके साथ खड़ा है, अमेरिका उनके लिए लड़ना जारी रखेगा।'

◇ जापानी भिक्षुओं ने तिब्बत में बुद्ध प्रतिमा विध्वंस करने पर चीनी शासन की निंदा की

tibet.net, ८ फरवरी २०२२

टोक्यो। जापानी भिक्षुओं के एसोसिएशन- सुपर संघ- के प्रतिनिधियों भिक्षु हयाशी शुई और भिक्षु कोबायाशी शुई ने जापान स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि आर्य त्सेवांग ग्यालपो के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर सुपर संघा के प्रतिनिधियों ने चीनी कम्युनिस्ट शासन द्वारा तिब्बत के खाम ड्रागो क्षेत्र से ९९ फुट की बुद्ध प्रतिमा, ३० फुट की बुद्ध मैत्रेय की प्रतिमा, ४५ प्रार्थना-चक्रों और तिब्बती मठवासी स्कूल के विध्वंस किये जाने पर आक्रोश और निराशा व्यक्त की। उन्होंने तिब्बत में क्रूर चीनी शासन से पीड़ित तिब्बतियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए एसोसिएशन की ओर से एक लिखित बयान प्रस्तुत किया।

प्रतिनिधि डा0 आर्य के साथ सुपर संघ के वेन हयाशी शुई और वेन कोबायाशी शुई

प्रतिनिधियों ने तिब्बत कार्यालय को यह जानकारी दिया कि बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन पर टोक्यो स्थित चीनी दूतावास में तिब्बतियों, उग्यूरों, दक्षिण मंगोलियाइयों और हांगकांग के निवासियों के साथ 'सुपर संघ' के सदस्यों ने भी विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उस समय भिक्षु कोबायाशी और भिक्षु वाकाओमी ने तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की निंदा करते हुए एसोसिएशन द्वारा जारी बयान का वाचन किया और इसे चीनी दूतावास को सौंपा।

प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने 'सुपर संघ' के प्रतिनिधियों को धन्यवाद करते हुए तिब्बत मुद्दे के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सराहना की। सुपर संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि जापानी भिक्षुओं के लिए यह स्वाभाविक है कि वे बुद्ध की प्रतिमा को गिराए जाने और उनकी शिक्षाओं को अपवित्र किए जाने पर चीन का विरोध करते रहेंगे क्योंकि जापानी भिक्षु बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपना धर्म मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल तिब्बत में दमन और क्रूरता का मामला नहीं है बल्कि यह बौद्ध धर्म पर सीधा हमला है।

चीनी राजदूत को प्रस्तुत किये गये 'सुपर संघ' का बयान में लिखा कि, 'यह खेदजनक है कि शांति का त्योहार माने जाने वाले ओलंपिक खेलों से ठीक पहले आपकी सरकार ने एक बार फिर से नस्लीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में धार्मिक उत्पीड़न को तेज कर दिया है और ड्रागो खाम में बौद्ध प्रतिमाओं का विध्वंस करने के साथ ही प्रार्थना-चक्रों को नष्ट किया है।

इसमें कहा गया है, 'तिब्बती बौद्ध धर्म संपूर्ण मानव जाति की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, जिसका इतिहास १५०० साल पुराना है। इसलिए हम दुनिया भर के बौद्ध आपकी सरकार द्वारा धर्म और मानवाधिकारों के दमन का विरोध करते हैं। इसका कारण चाहे जो रहा हो।'

◇ तिब्बत पर जर्मन संसदीय समूह ने नए विधायी कार्यकाल के दौरान पहली बैठक बुलाई

tibet.net, १२ फरवरी २०२२

जिनेवा। तिब्बत पर जर्मन सर्वदलीय संसदीय समूह अर्थात जर्मन क्रॉस पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत ने २०वें विधायी कार्यकाल की अपनी पहली संगठनात्मक बैठक १० फरवरी को आयोजित किया था। संसदीय समूह ने सांसद माइकल ब्रांड (सीडीयू) को अपना अध्यक्ष चुना। समूह के जर्मन संसद के सदस्य- सांसद मारिया क्लेन-शमींक (ब्रुंडनिस ९०/ग्रीन्स), सांसद पीटर हेइड्ट (एफडीपी) और सांसद नादजा स्टामर (एसपीडी) को संसदीय समूह के सह-अध्यक्ष के रुप में चुना गया।

तिब्बत मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास का संकल्प व्यक्त करते हुए समूह के अध्यक्ष सांसद ब्रांड ने जर्मन संसद में तिब्बत और तिब्बती लोगों के लिए 'स्पष्ट राजनीतिक पहल' तय करने की घोषणा की। बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में सांसद ब्रांड ने कहा कि चीनी शासन द्वारा तिब्बती लोगों पर लगातार बढ़ते दमन और उत्पीड़न को 'चुपचाप अनदेखा करना' बंद करने का

जर्मन संसद

समय आ गया है।

तिब्बत ब्यूरो के प्रतिनिधि छिमे रिग्ज़ेन ने तिब्बत और तिब्बती लोगों के लिए अटूट समर्थन और एकजुटता के लिए संसदीय समूह के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आने वाले वर्षों में तिब्बत मुद्दे को सबसे आगे लाने और जर्मन संसद-बुंडेस्टाग- में तिब्बती मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए संसदीय समूह की प्रतिबद्धता के लिए गहरा आभार व्यक्त किया।

◇ यूएनपीओ महासचिव ने तिब्बत कार्यालय का दौरा किया

tibet.net, १५ फरवरी २०२२

प्रतिनिधि ताशी फुंत्सोक और रिगजिन गेंखांग के साथ यूएनपीओ के महासचिव राल्फ बुन्चे

ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ताशी फुंट्सोक और यूरोपीय संघ के वकालत अधिकारी रिगज़िन जेनखांग ने १५ फरवरी को 'गैर प्रतिनिधित्व वाले देशों और लोगों का संगठन (यूएनपीओ)' के महासचिव श्री राल्फ बंच से मुलाकात की। अपनी डेढ़ घंटे की बैठक के दौरान उन्होंने साझा हित के पांच क्षेत्रों और भविष्य के सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की।

यूएनपीओ के तीन संस्थापक सदस्यों में से तिब्बत के एक होने के नाते तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ताशी फुंट्सोक ने इस वर्ष के अंत में परम पावन दलाई लामा और मध्यम मार्ग नीति पर संगठन की ओर से कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की।

मिस्टर बंच स्वर्गीय मिस्टर राल्फ जॉनसन बंच के पोते हैं, जो एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक, राजनयिक और २०वीं सदी के मध्य में उपनिवेशीकरण प्रक्रिया और अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वह इज़रायल में अपने मध्यस्थता कार्य के लिए १९५० में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी-अमेरिकी भी थे।

गुरुवार ११ फरवरी को यूरोपीय संघ के एडवोकेसी अफसर रिगज़िन जेनखांग ने यूएनपीओ प्रेसीडेंसी बैठक में भाग लिया, जो वस्तुतः इस साल कोविड -१९ महामारी के कारण फिर से हुई। यह बैठक वर्ष में कई बार होती है और इन बैठकों में संगठन की प्रगति, चुनौतियों और गतिविधियों पर चर्चा की जाती है।

◇ वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंध समिति के अधिकारियों से मुलाकात की

tibet.net, १६ फरवरी २०२२

प्रतिनिधि नामग्याल छोहडुप ने अमेरिका सीनेट समिति के विदेश संबंध अधिकारियों के सथ ऑनलाइन मुलाकात की

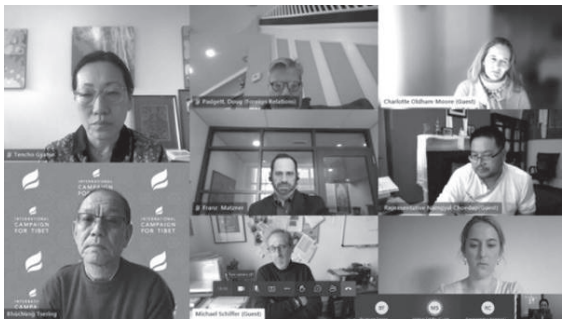

वाशिंगटन। वाशिंगटन डी.सी. स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्याल छोहडुप, सचिव ताशी धोंडुप, तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईसीटी) के अंतरिम निदेशक भुचुंग छेरिंग, आईसीटी अंतरिम उप निदेशक तेनचो ग्यात्सो और आईसीटी के सरकारी संबंध अधिकारी फ्रांज मैटज़नर ने अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंध समिति के वरिष्ठ अधिकारियों शार्लोट ओल्डम मोर, माइकल शिफ़र, विधायी और नीति विश्लेषक मौली बार्लो, ब्रुकिंग्स लेजिस्लेटिव फेलो सरडन सादिकोविक और विधान एवं नीति विश्लेषक डगलस लेविंसन के साथ ऑनलाइन मुलाकात की।

तिब्बती प्रतिनिधियों ने बैठक में वर्तमान सीटीए प्रशासन की मध्यम मार्ग दृष्टिकोण नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के बारे में बताया और इस बात को स्पष्ट किया कि यह किस प्रकार से चीन-तिब्बत मुद्दे को हल करने का एकमात्र व्यवहार्य साधन है। उन्होंने नए सीटीए प्रशासन द्वारा की गई पहल जैसे चीन-तिब्बत वार्ता की समाधान हेतु गठित स्थायी रणनीतिक समिति, स्वैच्छिक तिब्बत हिमायत समूह (वी-टैग) तथा तिब्बत के समर्थन में नेटवर्क को अधिक मजबूत करने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अमेरिकी और चीनी युवा पीढ़ी के बीच संबंध को बढ़ाने पर जानकारी साझा की। उन्होंने परम पावन दलाई लामा के दृष्टिकोण के तहत चीनी और तिब्बती समाजों के बीच बेहतर समझ विकसित करने के लिए युवा चीनी छात्रों तक पहुंच बनाने के महत्व पर जोर दिया।

इस बैठक में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा कानून में पारित तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम के आधार पर सीनेट की विदेश संबंध समिति से प्रतिक्रिया और समर्थन प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

◇ प्रतिनिधि नामग्याल छोहडुप ने अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत रशद हुसैन से मुलाकात की

tibet.net, १७ फरवरी २०२२

वाशिंगटन डी.सी.। तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्याल छोहडुप और सचिव ताशी धोंडुप ने १५ फरवरी २०२२ को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी एंबेसेडर-एट-लार्ज रशद हुसैन और कर्मचारी एलेक्स होगे से मुलाकात की। प्रतिनिधि छोहडुप ने राजदूत हुसैन और कर्मचारी एलेक्स होगे को बधाई दी और वर्तमान सीटीए प्रशासन, चीन-तिब्बत मुद्दे को हल करने के लिए मध्यम मार्ग नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और तिब्बती भाषा और धार्मिक अभिव्यक्ति सहित तिब्बती पहचान पर बीजिंग के लगातार हमलों के कारण तिब्बत के अंदर बिगड़ती स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राजदूत को चीन-तिब्बत वार्ता को पुनः प्रारंभ करने और तिब्बती मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाए गए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की पहल के बारे में जानकारी दी।

राजदूत हुसैन ने नवीनतम जानकारियों के लिए प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और तिब्बत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए निरंतर समर्थन देने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने तिब्बत कार्यालय के साथ मिलकर काम करने और भविष्य में परम पावन दलाई लामा से मिलने की इच्छा व्यक्त की।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन

अक्तूबर २०१९ में पूर्व राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक ने धर्मशाला का दौरा किया था और परम पावन दलाई लामा और वरिष्ठ तिब्बती अधिकारियों से मुलाकात की थी।

तिब्बती प्रतिनिधियों ने राजदूत को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उनके साथ आने वाले समय में मिलकर काम करने की गहरी इच्छा व्यक्त की।

◇ ओओटी दक्षिण अफ्रीका ने 'तिब्बत क्यों मायने रखता है' शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन किया

tibet.net, २६ फरवरी २०२२

प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका स्थित तिब्बत कार्यालय ने 'अफ्रीका में तिब्बत बचाव पहल', 'दक्षिण अफ्रीका में तिब्बत सोसाइटी' और 'तिब्बत समर्थक समूह, केप टाउन' समेत विभिन्न तिब्बत समर्थक समूहों के सहयोग से २४ फरवरी २०२२ को एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था- तिब्बत क्यों मायने रखता है?' इसे तिब्बत टीवी द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से लाइव-प्रसारण किया गया था।

इस वेबिनार को प्रसिद्ध कनाडाई पत्रकार, लेखक और मेल्टडाउन इन तिब्बत जैसे कई पुस्तक के लेखक माइकल बकले और वरिष्ठ तिब्बती राजनयिक तथा परम पावन दलाई लामा के पूर्व विशेष दूत केल्सांग ग्यालत्सेन ने संबोधित किया था। अपने संबोधन में माइकल बकले ने पूरे तिब्बती पठार पर नियंत्रण स्थापित कर लेने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के साथ कई दशकों के अपने प्रत्यक्ष अनुभवों से प्राप्त अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।

माइकल ने एशियाई उपमहाद्वीप के लिए तिब्बत के पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कैसे चीन दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता पर विचार किए बिना तिब्बत के मीठे पानी के संसाधनों और खनिज भंडार का दोहन कर रहा है।

पूर्व विशेष दूत केलसांग ग्यालत्सेन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा, हालांकि यह मंगोल और मंचू साम्राज्यों में अलग-अलग रूप में चीन के राजनीतिक प्रभावों के तहत आया था। इसलिए, तिब्बत पर चीनी कब्जा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है और तिब्बतियों द्वारा प्रस्तुत की गई मध्यम मार्ग नीति के माध्यम से तिब्बती मुद्दे को हल कराने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है।

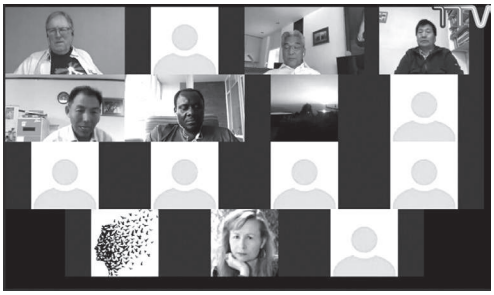

दक्षिण अफ्रिका तिब्बत कार्यालय

लगभग आधे घंटे के वेबिनार के दौरान इस बात पर भी गौर किया गया कि वेबिनार की कार्यवाही को कुछ दुर्भावनापूर्ण और बीमार मानसिकता के लोगों द्वारा हैक करने की कोशिश की गई और इसे काफी परेशान करने, प्रस्तुति पर अश्लील तस्वीरें डालने के कुत्सित कृत्यों द्वारा बाधित किया गया। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि इन बकवासों के पीछे कौन था, लेकिन हम अपराधियों की ऐसी घृणित हरकतों और मानसिकता से प्रभावित नहीं हुए।

वेबिनार लगभग पांच मिनट के बाद एक नए जूम लिंक पर जारी रहा और जीवंत प्रश्नोत्तर सत्र के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बेविनार के समापन पर प्रतिनिधि न्गोडुप दोरजी ने वेबिनार के उद्घाटन और समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी की।

◇ स्विस-तिब्बती समुदाय ने तिब्बत पर चीन के निरंतर कब्जे के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया

tibet.net, १४ फरवरी २०२२

जिनेवा। १३वें दलाई लामा द्वारा तिब्बती स्वतंत्रता की घोषणा के ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए स्विस-तिब्बती समुदाय ने १३ फरवरी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया।

इस अवसर पर तिब्बती समुदाय के सदस्य वहां एकत्र हुए और तिब्बत के ऐतिहासिक स्वतंत्र तथ्यों को उजागर करने के साथ ही तिब्बत पर चीन के निरंतर अवैध कब्जे का विरोध किया। इस अवसर पर उन्होंने तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत में गंभीर स्थिति को दर्शाने वाले बैनर लिए हुए थे। इसके अलावा, 'तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं था लेकिन मध्यम मार्ग एक व्यवहार्य समाधान है' शीर्षक वाले बैनर के साथ समुदाय के सदस्यों ने तिब्बत के ऐतिहासिक तथ्यों और चीन के नियंत्रण में रह रहे तिब्बती लोगों की वर्तमान स्थिति के साथ बीजिंग के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया।

तिब्बती समुदाय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, १३ फरवरी के इस अवसर को तिब्बत के ऐतिहासिक तथ्यों पर दोबारा गौर करने, बीजिंग के काले कारनामों को सफेद करने के

लिए उसके द्वारा चलाए जा रहे प्रचार तंत्र का प्रतिरोध करने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के उल्लंघन को उजागर करने के लिए किया।' प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि भले ही चीन तिब्बत में अपने काले कारनामों को सफेद करने का कितना भी प्रयास करें, तिब्बती और तिब्बत समर्थक उसकी सच्चाई को उजागर करना जारी रखेंगे।

स्विस तिब्बती समुदाय द्वारा विशाल प्रदर्शन

तिब्बत ब्यूरो के प्रतिनिधि छिमे रिग्ज़ेन, स्विट्ज़रलैंड और लिकटेंस्टीन के तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष कर्मा छोहएक्यी और जिनेवा-सेक्शन प्रभारी त्सेसुत्सांग योंगा ने तिब्बती समुदाय की सभा को संबोधित किया। आयोजन के वक्ताओं ने तिब्बत के जमीनी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ तिब्बत के न्यायोचित मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए समुदाय के सदस्यों के सामूहिक प्रयासों के समर्पण की सराहना की। स्विट्ज़रलैंड और लिकटेंस्टीन के तिब्बती समुदाय के उपाध्यक्ष तेनज़िन वांगडु ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

◇ सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसंग फेंडे और तेनजिन जिग्दल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की

tibet.net, २५ फरवरी २०२२

सांसद गोवो लोबसंग फेंदे और तेंजिन जिगड्रेल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात की

देहरादून। सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसंग फेंडे और तेनजिन जिग्दल ने देहरादून के अपने आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान आज २५ फरवरी को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री के साथ तिब्बती सांसदों की बैठक के दौरान देहरादून के कल्याण अधिकारी और भारत-तिब्बत समन्वय संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहे।

तिब्बती सांसदों ने मुख्यमंत्री से उनके समर्थन की अपील करते हुए उन्हें तिब्बतियों, विशेष रुप से देहरादून में तिब्बतियों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया।

निर्वासित तिब्बती संसद के कार्यक्रम के अनुसार, सांसद आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तिब्बती बस्ती के दौरे पर हैं। यह दौरा दरअसल नई निर्वासित तिब्बती संसद के गठन के बाद आम जनता से मिलने के कार्यक्रम का हिस्सा है। १३ फरवरी से शुरू हुई सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसंग फेंडे और तेनज़िन जिग्दल की अधिकारिक यात्रा कुछ दिनों में समाप्त होगी।

◇ कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया ने तिब्बत पर अपने काम को फिर से संगठित करने के लिए वर्चुअल बैठक आयोजित की

tibet.net, २५ फरवरी २०२२

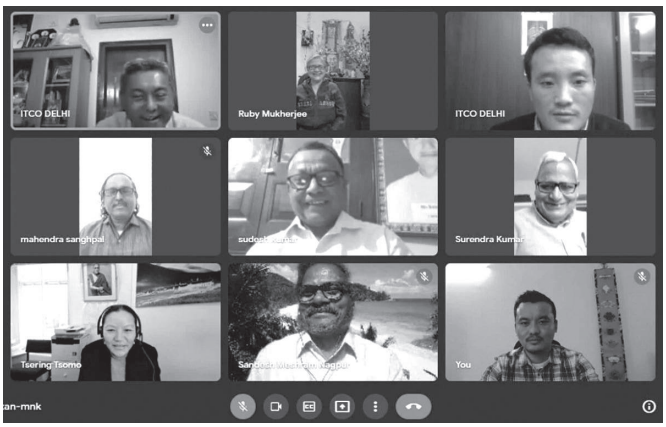

भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने कोर ग्रुप की संयोजकों का वेबिनार

नई दिल्ली। भारत में तिब्बत समर्थक समूहों की शीर्ष संस्था- कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज ने गुरुवार २४ फरवरी २०२२ को भारत-तिब्बत समन्वय केंद्र (आईटीसीओ) के समन्वय में अपने सदस्यों की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की। कोर ग्रुप की इस बैठक का मुख्य एजेंडा भारत में तिब्बत समर्थक समूहों द्वारा तिब्बती मुद्दे के संबंध में चल रहे अभियानों और परियोजनाओं को पुनर्गठित करना था। इसके अलावा, उप एजेंडे में प्रशासनिक स्थिति के बारे में नवीनतम ताजा जानकारियों से अवगत कराना था।

बैठक की शुरुआत करते हुए आईटीसीओ के कार्यक्रम अधिकारी छुनी छेरिंग ने कोविड महामारी के प्रकोप के बाद से दुनिया भर में आए बदलाव पर प्रतिभागियों को अवगत किया। साथ ही उन्होंने २०२० में गलवान की घटना के बाद से चीन-भारत संबंधों में अहम मोड़ और लगातार पीएलए सैनिकों की घुसपैठ का प्रयास चीन की बुरी मानसिकता के बारे में बताया और भारत सहित दुनिया के कई देशों द्वारा बीजिंग- २०२२ के शीतकालीन ओलंपिक के हालिया राजनयिक बहिष्कार के बारे में जानकारी साझा की।

उन्होंने आगे तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला। हाल ही में चीनी पुलिस द्वारा तिब्बत के ड्रैकगो में ९९ फीट की बुद्ध प्रतिमा और ४५ विशाल प्रार्थना-चक्रों को नष्ट करने, तिब्बतियों को गलत तरीके से हिरासत में लेने, भिक्षुओं और भिक्षुणियों को कैद करने और जेलों में यातना देने जैसे मुद्दों पर भी बैठक में चिंता जताई गई।

आईटीसीओ के उप समन्वयक तेनज़िन जॉर्डन ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान यानी अप्रैल- २०२१ से आईटीसीओ और तिब्बत समर्थक समूहों द्वारा की जा रही गतिविधियों, अभियानों और कार्यक्रमों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी।

इसके बाद कोर ग्रुप के सदस्यों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उनके द्वारा की गई गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में व्यक्तिगत रुप से जानकारी दी और तिब्बती मुद्दे को मजबूत करने के लिए भविष्य में उनके द्वारा की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों को भी रखा।

समन्वयक जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने सभी सदस्यों को तिब्बती मुद्दे के लिए उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया और अपना तबादला नए कार्यालय में होने के बारे में सूचित किया। उन्होंने तिब्बत मुक्ति साधना की इस यात्रा में सदस्यों के साथ अपने जुड़ाव के बारे में साझा किया और उनसे तिब्बती मुद्दे के लिए अपनी भावना को जीवित रखने का अनुरोध किया। उसी समय, उन्होंने नए समन्वयक छेरिंग त्सोमो से सदस्यों का परिचय कराया जो तिब्बत कार्यालय, लंदन से विशेष आमंत्रित के रुप में बैठक में शामिल हुई थीं।

छेरिंग त्सोमो ने सदस्यों के सामने अपना एक संक्षिप्त परिचय दिया और बताया कि वह सभी सदस्यों के साथ अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।

सीजीटीसी-आई के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सदस्यों ने तिब्बत मुक्ति साधना की यात्रा के दौरान मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए समन्वयक जिग्मे त्सुल्ट्रिम को हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने तिब्बती हित के लिए सभी भारतीय तिब्बत समर्थक समूहों को एक साथ लाने के उनके अथक कार्य और प्रयासों की सराहना की और उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

सदस्यों ने नए समन्वयक छेरिंग त्सोमो को बधाई दी और गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उनकी नई भूमिका और जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

अंत में उप समन्वयक तेनज़िन जॉर्डन ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने छेरिंग त्सोमो को अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया।

◇ कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया के असम के क्षेत्रीय संयोजक ने स्वर्गीय श्री नरेन चंद्र दास को श्रद्धांजलि दी

tibet.net, १० फरवरी २०२२

कोर ग्रुप तथा तिब्बत समन्वय केंद्र ने स्वर्गीत नरेन चंद्र दास के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की

बालीपारा (असम)। दिवंगत हवलदार श्री नरेन चंद्र दास- ५ असम राइफल्स रेजिमेंट के उन सात सैनिकों में से अंतिम जीवित सदस्य थे, जो उन लोगों में से कई के लिए ऐतिहासिक संदर्भ छोड़ गए हैं, जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, परम पावन दलाई लामा में विश्वास करते हैं और भारत और तिब्बत के बीच विशेष बंधन की आकांक्षा रखते हैं। श्री दास का २८ दिसंबर, २०२१ को बालीपारा से दो किलोमीटर और तेजपुर से २५ किलोमीटर दूर उनके गृह गांव उदमारी में निधन हो गया।

१४ मार्च १९५९ का दिन तिब्बत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था, जब परम पावन दलाई लामा को अपने देश- तिब्बत से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वह विश्रांत और थके हुए थे, लेकिन उनका यह विश्वास अडिग था कि गुरु होने के नाते भारत अपने शिष्य को शरण देगा। परम पावन दलाई लामा याद करते हुए कहते हैं कि ३१ मार्च १९५९ को नेफा (वर्तमान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर) पहुंचने के बाद जब उन्होंने असम राइफल के भारतीय अधिकारियों और सैनिकों को देखा तो उनमें व्याप्त भय और संदेह के बादल छंट गए और उनमें आशा, अस्तित्व और तिब्बती पहचान के प्रति आश्वासन का नवीन संचार हो गया था, जो बौद्ध आस्था और अभ्यास के मूल्यों में निहित है।

यहां श्री नरेन चंद्र दास का संदर्भ इसलिए आया कि उन्होंने ५ असम राइफल्स रेजिमेंट के छह अन्य सैनिकों के साथ परम पावन दलाई लामा को भारत-तिब्बत सीमा से अरुणाचल प्रदेश के लुमला तक पहुंचाया था। निधन से पहले श्री दास को गुवाहाटी के साथ-साथ धर्मशाला में विशेष रुप से २०१८ में 'थैंक यू इंडिया' कार्यक्रम के दौरान कई कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया गया था।

माननीय सिक्योंग श्री पेन्पा त्सेरिंग के हस्ताक्षर से जारी शोक-पत्र के साथ बालीपारा के उनके गांव उदमारी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इसे जनवरी, २०२२ के पहले सप्ताह में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन कोविड -१९ मामलों की अचानक वृद्धि के कारण इसे आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया (सीजीटीसी- आई) के असम और मेघालय के क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता के साथ 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' के स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था की। इस कार्यक्रम में बालीपारा के जिला परिषद सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता श्री मृणाल सैकिया, उदमारी के ग्राम प्रधान श्री जादाब दास, उदमारी के ग्राम सचिव श्री पंकज बोरा, श्री अंकुर दास उपस्थित हुए। इनके अलावा मीडिया समूह से- प्राग न्यूज और प्रेस क्लब, बालीपारा के

प्रमुख दीपज्योति कोच सैकिया, प्रेस क्लब, बालीपारा की सचिव और असोमिया प्रतिदिन की सुश्री निराला डेका, प्रतिदिन टाइम्स के श्री मिलन दास और नियोमिया बार्ता के श्री परंजल पी. बोरा उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्री दत्ता ने अपने संबोधन में तीन बिंदुओं को लेकर अभियान चलाने की अपनी दिली इच्छा को प्रकट किया - पहला, इस मुद्दे पर समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि सीमा कोई भारत और चीन के बीच नहीं है, बल्कि भारत की सीमा केवल तिब्बत के साथ लगती है। दूसरा, स्वर्गीय श्री नरेन चंद्र दास की विरासत और सेवा को न केवल उदमारी, बालीपारा में बल्कि पूरे असम में प्रचारित किया जाए। और तीसरा, स्थानीय समुदायों और फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम के समर्थकों के समर्थन से उनके सम्मान में एक स्तूप का निर्माण किया जाए जो पर्यटकों को आकर्षित करेगी। साथ ही न केवल परम पावन दलाई लामा के प्रति उनकी सेवाओं बल्कि तिब्बत के साथ भारत के गहरे संबंधों के लिए उनकी सेवाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करेगी।

श्री मृणाल सैकिया ने इस अवसर पर फिर से भरोसा दिलाया कि स्थानीय समुदाय और प्रशासन स्वर्गीय श्री दास की सेवाओं को भविष्य में समाज की स्मृति के इतिहास में यादगार बनाए रखने के लिए जो भी संभव होगा, करेंगे।

स्वर्गीय श्री नरेन चंद्र दास के ज्येष्ठ पुत्र श्री राजेंद्र दास को संबोधित शोक-पत्र स्वर्गीय श्री नरेन चंद्र दास के अन्य बेटे-बेटियों- श्री दीपक दास, श्री रूपक दास और सुश्री रीना भुइयां ने ग्रहण किया। स्वर्गीय दास के सबसे बड़े बेटे लखनऊ में एसएसबी में तैनात हैं।

१२१ घरों का एक छोटा सा गांव होने के नाते कोई भी कार्यक्रम में ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन स्वर्गीय श्री नरेन चंद्र दास के परिवार के १५ सदस्यों सहित समुदाय के ५० से अधिक सदस्यों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दर्जनों स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को कवर किया। यह स्वर्गीय श्री दास की सेवा के प्रति सराहना को दर्शाता है।

◇ फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम और अन्य तिब्बत समर्थक समूहों ने गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठक की

tibet.net, १२ फरवरी २०२२

गुवाहाटी। परम पावन दलाई लामा को १९५९ में असम में बालीपारा स्थित अपने पैतृक गांव उदमारी में ले जाने वाले स्वर्गीय हवलदार नरेन चंद्र दास की श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के बाद भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने वापस जाते समय असम की राजधानी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर १० फरवरी, २०२२ को बीटीएसएम समेत फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम और असम स्थित अन्य तिब्बत समर्थक समूहों के सदस्यों और तिब्बत समर्थकों के साथ आयोजित बैठक में हिस्सा लिया।

भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने वरिष्ठ पत्रकार रुपम बरुआ को सम्मान किया

इस बैठक में श्री सौम्यदीप दत्ता (कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया के क्षेत्रीय संयोजक और फ्री तिब्बत-ए वॉयस फ्रॉम असम के संयोजक), श्रीमती उर्वशी महंत (अध्यक्ष, बीटीएसएम असम), श्री रुपम बरुआ (लेखक और वरिष्ठ पत्रकार), श्री नवा ठाकुरिया (वरिष्ठ पत्रकार), श्रीमती नोवनिता शर्मा (समन्वयक, फ्री तिब्बत-ए वॉयस फ्रॉम असम), सदस्यों और व्यक्तिगत तिब्बत समर्थकों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान 'फ्री तिब्बत-ए वॉयस फ्रॉम असम' ने ब्रह्मपुत्र नदी के तट से अपना समाचार पत्र 'त्सांगपो-सियांग- ब्रह्मपुत्र' लॉंच किया। अंग्रेजी और असमिया भाषा में प्रकाशित होने वाला यह द्विभाषी समाचार पत्र इस जन मंच द्वारा अब तक की गई गतिविधियों और गतिशीलता की पैरोकारी का प्रतिनिधित्व करता है। यह गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में व्यापक सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से तिब्बती स्वतंत्रता के मुद्दों के बारे में आयोजित की जाती हैं। यह मंच असम और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रभावी जागरूकता के माध्यम से एक जन आंदोलन को संगठित कर रहा है।

'त्सांगपो- सियांग- ब्रह्मपुत्र' फ्री तिब्बत - ए वॉयस फ्रॉम असम का समाचार पत्र भविष्य में भी असम और पूरे भारत के लोगों को तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ते रहने को प्रतिबद्ध है। फ्री तिब्बत-ए वॉयस फ्रॉम असम के संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता ने कहा कि शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र से समृद्ध भूमि- असम ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल तिब्बत को बचाने और मुक्त करने के लिए उठ खड़ा होगा।

बैठक के दौरान लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और उत्साही तिब्बत समर्थक श्री रुपम बरुआ को सदस्यों द्वारा तिब्बती हित में लंबे योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

सदस्यों ने पूर्वोत्तर भारत में तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा की और विशेष रुप से तिब्बत से निकलने वालें ब्रह्मपुत्र नद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आने वाले दिनों में तिब्बत जागरूकता अभियान चलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग से असम में धुबरी तक साइकिल रैली की रुपरेखा पर चर्चा की।

◇ शिलांग कल्याण अधिकारी पेमा धोंडुप ने राजभवन में मेघालय के राज्यपाल से मुलाकात की

tibet.net, १७ फरवरी २०२२

शिलांग। शिलांग के तिब्बती कल्याण अधिकारी श्री पेमा धोंडुप ने १६ फरवरी २०२२ को मेघालय के माननीय राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। निर्वासित तिब्बती संसद की सदस्य श्रीमती त्सेरिंग डोल्मा ने स्थानीय तिब्बती मठ के महंत और कल्याण अधिकारी के साथ मेघालय के राज्यपाल को कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में पारंपरिक खटक (सफेद दुपट्टा) और स्मृति चिन्ह भेंट किया।

शिलोंग तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने मेघालय के राज्यपाल माननीय सत्य पल मालिक के साथ मुलाकात की

सांसद छेरिंग डोल्मा ने तिब्बती संसद की ओर से बधाई दी और आभार प्रकट किया और मार्च में आने वाले संसद सत्र के बारे में माननीय राज्यपाल को जानकारी दी। इसके अलावा, उन्होंने तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला, जिसके लिए राज्यपाल ने तिब्बत के न्यायोचित मुद्दे के प्रति अपनी एकजुटता जताई।

श्री पेमा धोंडुप ने भारत और तिब्बत के बीच आध्यात्मिक संबंधों के बारे में जानकारियां दी और नालंदा परंपरा से प्रबुद्ध भारतीय विद्वानों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, जिसने तिब्बत को बौद्ध धर्म का प्रकाश दिया। महामहिम राज्यपाल ने परम पावन दलाई लामा के साथ अपनी मुलाकात का स्मरण किया और परम पावन दलाई लामा के साथ बिताए क्षणों को याद कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

सांसद और कल्याण अधिकारी ने नए मठ सह सांस्कृतिक केंद्र के चल रहे निर्माण के बारे में जानकारी दी जिसका उद्देश्य सौहार्दता, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, संतोष, शांति और अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित प्राचीन नालंदा परंपरा को एक दयालु और शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए एक केंद्र प्रदान करना है। माननीय राज्यपाल ने नए मठ और सांस्कृतिक केंद्र के उद्देश्यों और विषयों की सराहना की।

अंत में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से सांसद और कल्याण अधिकारी दोनों ने भारत सरकार और राज्य सरकार को उनके गहन समर्थन और करुणापूर्ण आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया।

◇ श्री त्सेरिंग येशी द्वारा तिब्बत के लिए 'राइड फॉर प्राइड' बाइक अभियान का दिल्ली में समापन

tibet.net, १७ फरवरी २०२२

दिल्ली। तिब्बत के लिए 'राइड फॉर प्राइड' के तहत हिमाचल प्रदेश से तमिलनाडु और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक १९,००० किलोमीटर से अधिक की यात्रा के दौरान भारत के लगभग सभी राज्यों को कवर करने के बाद छेरिंग येशी का बाइक अभियान अंततः १६ फरवरी,

भारत तिब्बत सहयोग मंच और भारत तिब्बत संवाद मंच के सदस्यों ने "राइड फॉर प्राइट बाइक रैली" के समापन समारोह में भाग लिया

२०२२ को दिल्ली में संपन्न हो गया। इस अवसर पर भारत-तिब्बत समन्वय केंद्र दिल्ली द्वारा समन्वित रोहिणी के तिब्बती युवा छात्रावास में एक संक्षिप्त समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) के महासचिव श्री पंकज गोयल सहित तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) के सदस्यों ने भाग लिया। इनमें बीटीएसएम दिल्ली के अध्यक्ष श्री अनिल मोंगा, बीटीएसएम के कार्यकारिणी सदस्य श्री राधे श्याम, भारत-तिब्बत संवाद मंच- दिल्ली के अध्यक्ष श्री अभिषेक जैन, आईटीसीओ दिल्ली के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम और कर्मचारी तथा तिब्बती युवा छात्रावास के छात्र शामिल थे।

समन्वयक जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रावास के सभी छात्रों और तिब्बत समर्थक समूहों के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने त्सेरिंग येशी द्वारा २२ मार्च, २०२१ से शुरू किए गए अभियान के बारे में परिचय दिया, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से शुरू होकर पूरे भारत में तिब्बत के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है।

छेरिंग येशी को बाद में तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों और छात्र परिषद, तिब्बती युवा छात्रावास के अध्यक्ष ने 'हैंड्स ऑफ तिब्बत, कम्युनिस्ट चाइना' नामक स्मारिका प्रस्तुत कर गौरवान्वित और सम्मानित किया।

श्री पंकज गोयल ने अपने दम पर तिब्बत के लिए अभियान चलाने के लिए त्सेरिंग येशी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि तिब्बत के लिए काम

करना प्रत्येक तिब्बतियों का कर्तव्य है और बताया कि जब तक तिब्बत कम्युनिस्ट चीन के बुरे हाथों से मुक्त नहीं हो जाता, वह एक भारतीय होने के नाते तिब्बत के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि तिब्बत की स्वतंत्रता भारत की सुरक्षा है।

श्री अभिषेक जैन ने छेरिंग येशी से मिलकर खुशी का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि कोई आपकी भूमि पर कब्जा कर सकता है, लेकिन अगर देश के लिए आपकी भावना आपके अंदर जीवित है, जैसा कि छेरिंग येशी ने अपने काम के माध्यम से दिखाया है, तो वह दूर नहीं है जब आपको अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। उन्होंने छात्रों से तिब्बत के लिए भावना को जीवित रखने और अपनी भूमि के लिए लड़ते रहने का आग्रह किया।

छेरिंग येशी ने अपने संबोधन में 'बाइक राइड' अभियान के पीछे के उद्देश्य और अपनी अभियान यात्रा के पूरे अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान दो कारणों से चलाया गया था। सबसे पहले, परम पावन १४वें दलाई लामा द्वारा पिछले 60 वर्षों से तिब्बत मुद्दा तथा तिब्बती लोगों के प्रति मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद हेतु कृतज्ञता प्रकट करना हैं। दूसरा, तिब्बत मुद्दे की हित के लिए काम करने के लिए प्रत्येक तिब्बती को जागृत करना क्योंकि यह केवल तिब्बती प्रशासन और अन्य संगठनों का ही कर्तव्य नहीं है कि वे हमेशा तिब्बत के लिए अभियान चलाए बल्कि यह प्रत्येक तिब्बतीयों का भी कर्तव्य है।

येशी को यह बताते हुए खुशी हो रही थी कि अपने अभियान के दौरान वे जहां भी गए, तिब्बतियों और भारतीयों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया गया। उन्होंने अपने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद और समर्थन के लिए भारत के सभी तिब्बत समर्थक समूहों के सदस्यों, तिब्बती कल्याण कार्यालय, तिब्बती गैर सरकारी संगठनों, छात्र संघों और अन्य सभी व्यक्तियों को धन्यवाद दिया।

छेरिंग येशी ने छात्रों से कहा कि उन्होंने तिब्बती युवा छात्रावास में अपने अभियान को समाप्त करने का विकल्प चुना, क्योंकि उनका मानना है कि छात्र देश के भविष्य हैं और उनके साथ बातचीत करने से भविष्य में और अधिक परिणाम सामने आएंगे क्योंकि छात्र युवा और ऊर्जावान हैं और आजकल अधिक स्मार्ट भी हैं। उन्होंने उनसे तिब्बत पर होने वाली किसी भी गतिविधियों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया क्योंकि वे तिब्बत के लिए और अधिक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने उनसे कॉलेजों में अपने भारतीय मित्रों के साथ अधिक जुड़ने और तिब्बत की कहानी सुनाकर सामान्य भारतीय युवाओं में जागरूकता पैदा करने की अपील की।

समन्वयक जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी का और विशेष रूप से छात्रों को वक्ताओं को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कार्यक्रम की मेजबानी की पूरी व्यवस्था करने के लिए तिब्बती युवा छात्रावास प्रशासन को भी धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम का समापन तिब्बती और भारतीय राष्ट्रगान के भावपूर्ण गायन के साथ हुआ।

◇ एसएफएफ के शहीद डिप्टी लीडर तेनज़िन नोरबू भारत में वीरता सेवा के लिए सम्मानित

tibet.net, १९ फरवरी २०२२

शिलांग। वर्ष १९८८ में सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए एसएफएफ के दिवंगत डिप्टी लीडर तेनजिन नोरबू को मेघालय के बीएन एनसीसी ऑफ असम रेजिमेंट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और उनकी वीरता सेवा के लिए भारत सरकार की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।

दिवंगत डिप्टी लीडर तेंजिन नोरबू को मेघालय के बीएन एनसीसी ऑफ असम रेजिमेंट ने "गार्ड ऑफ ऑनर" से सम्मानित की

शहीद डिप्टी लीडर के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें उनकी पत्नी छेरिंग भूटी, पुत्र तेनज़िन दावा और परिवार के सदस्य शामिल हुए।

तिब्बती कल्याण अधिकारी पेमा धोंडुप ने शहीद तेनज़िन नोरबू को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार और असम रेजिमेंट को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे भारत और तिब्बती जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और बलिदान के लिए सलाम किया और उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

◇ तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी में जन आंदोलन

mahabahu.com, नोवनीता शर्मा

कम्युनिस्ट चीन द्वारा १९५० के दशक में तिब्बत पर कब्जे करने और उसके बाद तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों पर लगातार अत्याचार तथा कठोर नियंत्रण चलाए जाने के कारण तिब्बत मुक्ति साधना का जन्म हुआ था। मार्च १९५९ में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह ने पूरे तिब्बत को तिब्बती मुक्ति साधना की आगोश में खींच लिया। परम पावन १४वें दलाई लामा के भारत में निर्वासित होने के परिणाम स्वरूप लाखों तिब्बतियों ने भारत और अन्य देशों में शरणार्थियों के रूप में पलायन किया, जिन्होंने आनेवाले वर्षों में तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कई अलग-अलग देशों के समर्थन को धीरे-धीरे समेकित किया। अहिंसा और मानवता के मूल्यों में दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण तिब्बती मुक्ति साधना ने वैश्विक समुदाय से उचित सम्मान और समर्थन अर्जित किया। मानव इतिहास में अब तक देखे गए सबसे दमनकारी शासनों में से एक के खिलाफ तिब्बतियों (जिसमें तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों के साथ-साथ दुनिया भर में फैले तिब्बती प्रवासी शामिल हैं) का यह दृढ़ अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन सबसे बड़ी मानवीय सहनशक्ति और पूरे मानव इतिहास में दृढ़ता का अप्रतिम उदाहरण है। तिब्बती मुक्ति साधना का यह अनुकरणीय लचीलापन लगभग आठ अरब मनुष्यों में आशा का संचार करता है। तिब्बत में

चीन के ७० वर्षों के निरंकुश शासन के तहत तिब्बतियों की जीवन, संपत्ति और विरासत की अपूरणीय क्षति हुई है। अब तक चीनी अधिकारियों द्वारा १० लाख तिब्बतियों को मार डाला गया है और हजारों मठों को नष्ट कर दिया गया है। चीनी शासन के तहत तिब्बत की इस सुनियोजित सांस्कृतिक और नस्लीय संहार के विरोध में शांतिपूर्ण तिब्बतियों ने अपने आप को आत्मा-बलिदान दिया है। दमनकारी चीनी नीतियों और तिब्बत में उसके क्रूर शासन के विरोध में अब तक १५४ तिब्बतियों ने आत्मदाह कर शहादत हासिल की है। तिब्बत में तिब्बतियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं का सामना करना किसी भी सभ्य समाज की कल्पना से परे है। इस तरह के अत्याचारों के बावजूद तिब्बतियों ने अपने राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता और न्याय के लिए वास्तव में अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और ताकत दिखाई है। इस तिब्बती भावना को सलाम। यह अदम्य आत्मा कभी भी बहुत अधिक समय तक बेड़ियों में नहीं बंधी, चाहे दमनकारी कितना भी शक्तिशाली और बर्बर क्यों न रहा हो।

भारत में तिब्बती मुक्ति साधना के बारे में परिदृश्य २०१९ तक अपरिवर्तित रहा। इस दौरान यह मानवतावादी प्रभाव के साथ राजनीतिक अभियान के रूप में अस्तित्व में बना रहा, इस कारण यह आम भारतीय नागरिकों के मानस में नहीं आ पाया। जो लोग तिब्बती मुक्ति साधना में शामिल थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में भारतीय नागरिकों की भागीदारी के महत्व पर जोर नहीं दिया। वर्ष २०२० तिब्बती मुक्ति साधना के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में सामने आया है। पहला, कोविड-१९ महामारी की अनिश्चितताओं से भरे इस वर्ष ने दुनिया के सामने कम्युनिस्ट चीनी शासन की बुराइयों को उजागर कर दिया और दूसरा, इस वर्ष तिब्बत के शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में भारत में एक सच्चे जन आंदोलन का उदय हुआ। असम इस जन आंदोलन का मुख्य केंद्र है, जिसकी शुरुआत २०२० से 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' नामक एक जन मंच द्वारा तिब्बत और तिब्बती मुक्ति साधना के बारे में संवेदनशीलता के साथ जनता के बीच जोरदार जागरूकता फैलाने के साथ हुई थी। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और लेखक (कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया के असम और मेघालय के क्षेत्रीय संयोजक) श्री सौम्यदीप दत्ता के नेतृत्व में मंच के साथ लंबे समय से तिब्बत समर्थक, वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, पर्यावरण कार्यकर्ता, लेखक, कवि, कलाकार, छात्र, असम के नागरिक समाज के प्रतिनिधि और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' ने आम लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में तिब्बती मुक्ति साधना को मजबूत करने की दृष्टि से अपनी यात्रा शुरू की। मंच ने भारत में तिब्बत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तिब्बती मुक्ति साधना का समर्थन करने वाले एक जन आंदोलन को खड़ा करने की परिकल्पना की है। सुदूर पूर्वोत्तर भारत में तिब्बती मुक्ति साधना की यह ताजा चिंगारी ३० दिसंबर २०२० से १० जनवरी २०२१ तक असम के गुवाहाटी में ३३वें गुवाहाटी पुस्तक मेले में आयोजित एक अद्वितीय 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' स्टाल के रूप में सामने आई। स्टाल ने असम और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के बीच तिब्बती मुक्ति साधना के लोकाचार को सफलतापूर्वक फैलाया। इस स्टाल के साथ फोरम ने ३० सदस्यीय तिब्बती सांस्कृतिक दल को ३३वें गुवाहाटी पुस्तक मेले में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया, ताकि पूर्वोत्तर भारत के लोगों को तिब्बत की समृद्ध संस्कृति से जोड़ा जा सके और इस प्रकार तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। तिब्बती सांस्कृतिक मंडली ने तिब्बत के पारंपरिक नृत्य और संगीत के अपने सुंदर प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन सांस्कृतिक प्रदर्शनों ने तिब्बत और असम सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक समानता का दर्शन कराया। दर्शकों को दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए समान लोक संगीत, वाद्ययंत्र, संगीत और नृत्य के रूप में सामग्री और सांस्कृतिक आधार मिल गए थे जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण वार्षिक साहित्यिक कार्यक्रम होने के नाते गुवाहाटी पुस्तक मेले ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तिब्बती मुक्ति साधना की लहरों को फैलाने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया। मंच ने २०२० में अपनी स्थापना के बाद से पूर्वोत्तर भारत में जन आंदोलन को फैलाने के लिए तिब्बती मुक्ति साधना में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपना संचालन जारी रखा। मंच की गतिविधियों को मीडिया में अच्छी तरह से कवर किया गया। असम और पूर्वोत्तर भारत के आम नागरिकों के बीच पारिस्थितिकीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की एकरूपता और पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थिति तिब्बत के बारे में आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करता है। मंच के सदस्यों द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय लेखों के साथ-साथ स्थानीय भाषा में प्रकाशित शैक्षिक उपकरण, वेबिनार, व्याख्यान और मंच द्वारा आयोजित अन्य सार्वजनिक बातचीत ने पूर्वोत्तर भारत में जागरूकता और पैरोकारी अभियान को और मजबूत किया। तिब्बत के बारे में बढ़ती जागरूकता और इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण तिब्बती मुक्ति साधना ने असम और पूर्वोत्तर भारत में संभावित जन आंदोलन के लिए राज्य भर से असम के वृहत्तर समाज के समर्थन और भागीदारी को समेकित किया। लोगों की भागीदारी की इस लहर ने असम को ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट से लेकर राज्य भर में सभी दिशाओं में बहा दिया। यह जन आंदोलन असम और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न नस्लीय समुदायों में प्रवेश कर रहा है। इसके प्रति युवाओं, छात्रों, ग्रामीणों, महिलाओं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों सहित आम जनता के बीच समर्थन आधार बढ़ रहा है।

तिब्बत को अक्सर एशिया के जल मीनार के रूप में वर्णित किया जाता है। एशिया की कई प्रमुख नदियां तिब्बती पठार से निकलती हैं, जो तिब्बत को भारत और एशियाई देशों की जल सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं। असम की लंबाई में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के हिमालयी हिमनदों से निकलती है। इसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है जो नीचे की ओर अरुणाचल प्रदेश में बहती आती है और सियांग नदी कहलाती है। यहां से यह ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में असम में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलने वाली यह नदी नीचे की ओर बहती है और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले मानव निवास क्षेत्रों में से एक को समृद्ध करती है। यह क्षेत्र दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जो वैश्विक महत्व की समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस प्रकार, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र सभ्यता के लिए आर्थिक, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक जीवन रेखा बनाती है जो तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो से शुरू होती है और असम और उसके बाहर ब्रह्मपुत्र नदी तक जीवन में रंगीन उत्सव को शामिल करती है। कम्युनिस्ट चीनी शासन तिब्बत की नाजुक पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहा है। इसने जंगलों, वन्यजीवों, घास के मैदानों को इस तरह से तबाह कर दिया गया है कि इनका पुनर्जीवन असंभव है। इसी तरह तिब्बती पठार से निकलने वाली हिमालयी नदियों पर नासमझ बांध बनाकर लाखों लोगों की भविष्य की पारिस्थितिकीय और आर्थिक सुरक्षा और निचले इलाकों के देशों में जीव जगत के अन्य रूपों को खतरे में डाल दिया गया है। इसमें यारलुंग त्सांगपो- सियांग-ब्रह्मपुत्र के प्रवाह की जद में आनेवाली ब्रह्मपुत्र सभ्यता भी शामिल है। पर्यावरण कानूनों की पूर्ण अवहेलना के साथ इस दमनकारी शासन ने ग्रह पर

सबसे ऊंचे पठार की पारिस्थितिकी को तबाह कर दिया है और वे इतने पर ही नहीं रुकेंगे। उनका शोषण मॉडल एशिया की पारिस्थितिकी तबाही के लिए एक निश्चित नुस्खा है जिसे बहुत देर होने से पहले रोक दिया जाना चाहिए। कम्युनिस्ट चीनी शासन के चंगुल से तिब्बत की स्वतंत्रता तिब्बत की पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है जो ब्रह्मपुत्र सभ्यता के लिए भी सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। कम्युनिस्ट चीन इस जल वर्चस्व के साथ धोखे से क्षेत्रीय आधिपत्य का कार्ड खेलता है, जो एशियाई देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय धमकी के रूप में कार्य करता है। घनी आबादी वाले एशियाई देशों के लिए जल सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अब तक सभी राजनीतिक दलों ने बहुत ही सूक्ष्मता से टाला है। कम्युनिस्ट चीन के जबरदस्त राजनीतिक वर्चस्व से संबंधित ये मुद्दे तिब्बती मुक्ति साधना से निकटता से जुड़े हुए हैं। तिब्बती मुक्ति साधना का कारण सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं है, यह एक पर्यावरणीय अभियान भी है, जिसके गहरे मानवीय निहितार्थ हैं। तिब्बत के पड़ोसी देशों में रहने वाले लाखों लोगों की भविष्य की पारिस्थितिकी और आजीविका सुरक्षा के साथ-साथ तिब्बत के पर्यावरण की तबाही के बारे में गंभीर होती हकीकत पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है और न ही इसके लिए पैराकारी की जा रही है, जो कि इसके लिए बहुत ही जरूरी है। पहली बार, यह 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' जैसे फोरम की सक्रिय पैरोकारी के कारण प्रासंगिक मुद्दा भारत में तिब्बती मुक्ति साधना का अभिन्न अंग बन गया है। असम में स्थित यह मंच तिब्बत के पारिस्थितिकीय महत्व के बारे में असम और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के बीच जागरूकता और गहरी समझ पैदा कर रहा है और कम्युनिस्ट चीन के पारिस्थितिकीय तबाही के डिजाइन से सियांग/ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को बचाने के लिए तिब्बती मुक्ति साधना के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। यह तिब्बत में अपने मूल रूप में बड़ा है। 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' विभिन्न गतिविधियों और प्रकाशनों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र सभ्यता की बेहतर समझ को सुगम बनाकर तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। ब्रह्मपुत्र सभ्यता के बारे में मंच द्वारा जागरूकता अभियानों ने अब तक तिब्बती मुक्ति साधना में पूर्वोत्तर भारत के लोगों का समर्थन और उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। लोग संस्कृतियों के बीच घनिष्ठ संबंध महसूस करते हैं और वे तिब्बत की सुंदर विरासत और इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। अपने निरंतर प्रयासों और दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' ने भारत में अब तक शांतिपूर्ण तिब्बती मुक्ति साधना में भारतीय भागीदारी के सबसे गतिशील प्रतिबिंब को जन्म दिया है। परम पावन ने अपने ६३ वर्षों के निर्वासित जीवन में तिब्बती मुक्ति साधना की भावना को हर जगह पहुंचाया। मार्च १९५९ में असम और पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार से तिब्बती मुक्ति साधना का यही सार भारत की धरती पर पहुंचा और यहां से दुनिया भर में फैल गया। तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में जन आंदोलन का उदय कार्मिक संबंध जैसा लगता है। 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' की अगुआई में पूर्वोत्तर भारत के इस जन आंदोलन ने भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर मिसाल कायम की, जिससे उन्हें तिब्बती मुद्दे को सार्थक समर्थन देने का तरीका दिख रहा है। तिब्बती मुक्ति साधना बुराई के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई है और एक राष्ट्र के रूप में भारत ने हमेशा सत्य और ज्ञान के प्रकाश के साथ दूसरों का नेतृत्व किया है। इन वास्तविकताओं से अवगत होने के बाद प्रत्येक भारतीय स्वेच्छा से अपनी भागीदारी से तिब्बती मुक्ति साधना को मजबूत करने को तत्पर होगा। 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' ने मशाल जलाई है। उत्तर-पूर्वी भारत में इस जन आंदोलन का उदय ६० लाख तिब्बतियों के लिए आशा की एक किरण के समान है। तिब्बती मुक्ति साधना ने आखिरकार भारत में मजबूत पैर जमा लिया है, ब्रह्मपुत्र सभ्यता से यह जन आंदोलन दुनिया भर से तिब्बती मुक्ति साधना के समर्थकों के लिए नई दशा-नई दिशा सुनिश्चित करता है। भोड़ ग्यालो !!

(लेखक पर्यावरण कार्यकर्ता और 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम' की समन्वयक हैं।)

◇ बुद्ध प्रतिमा का विध्वंसः कैसे शी जिनपिंग तिब्बत में पारंपरिक बौद्ध धर्म को नष्ट कर रहे हैं

३ फरवरी २०२२, tibetpolicy.net
छेरिंग डोल्मा

शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत में पारंपरिक बौद्धों और बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां तक कि वहां सबसे प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को भी नष्ट किया गया है।

तालिबान द्वारा २००१ में विशाल बामियान बुद्ध की मूर्तियों पर बमबारी के बीस साल हो चुके हैं। इसने न केवल दुनिया भर के लाखों बौद्धों की भावनाओं को आहत किया, बल्कि यह तालिबान शासन के त्वरित पतन और अफगानिस्तान को अगले दो दशकों तक निरंतर अराजकता और संघर्ष में झोंकने का भी कारण बना।

दुर्भाग्य से, तिब्बत में ९९ फीट ऊंची एक और विशाल बुद्ध प्रतिमा को १२ दिसंबर २०२१ को तालिबान द्वारा नहीं, बल्कि चीनी सरकार द्वारा नष्ट कर दिया गया। प्रतिमा का निर्माण स्थानीय चीनी सरकार से सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद पूर्वी तिब्बत में ड्रागो के स्थानीय समुदाय के योगदान से किया गया था। विशाल बुद्ध प्रतिमा के निर्माण का प्राथमिक कारण समुदाय द्वारा आगे की प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए दैवी कृपा का आह्वान करने का सामूहिक निर्णय था, क्योंकि इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व संख्या में जंगल की आग, भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन देखा गया था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, मूर्ति को नष्ट करने से पहले, चीनी सरकार ने एक स्कूल को भी जबरदस्ती ध्वस्त कर दिया, जहां से इस क्षेत्र में लगभग सौ छात्रों ने शिक्षा ली थी। इतना ही नहीं चीनी सरकार ने ४५ बौद्ध प्रार्थना-चक्रों को भी तोड़ दिया।

यह तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता के चीनी सरकार के दावे के बिल्कुल विपरीत है और पूरे तिब्बत में बेशुमार धार्मिक दमन का संकेत है। जिस क्षेत्र में प्रतिमा को गिराया गया है, उस क्षेत्र में दो चीनी काउंटी प्रमुखों द्वारा किए गए विनाश ने तिब्बतियों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचाया है। इस कारण से उनमें भय व्याप्त हो गया है और उनके दिलो-दिमाग में चीनियों के प्रति घृणा की स्थायी भावना गहरी हो गई है।

१९५१ के सत्रह सूत्री समझौते में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बती परंपरा और धर्म का सम्मान करने का वादा किया था। इस समझौते पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद हस्ताक्षर किया गया था।

हालांकि, चीन की दमनकारी कार्रवाई माओ की सांस्कृतिक क्रांति (१९६६-१९७६) के समय से ही लगातार तिब्बती बौद्ध धर्म पर कहर ढा रही है और नवंबर २०१२ में शी जिनपिन के सत्ता में आने के बाद नए उत्साह के साथ इस दमन को तेज किया गया है। इसी समय में चीन, तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान (झिंझियांग) और भीतरी मंगोलिया में भी कठोर दमन शुरू किया गया है। इस निरंतर उत्पीड़न ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए

उपलब्ध पहले से ही कम जगह को और कम कर दिया है, जिससे स्थिति पूरी तरह खराब हो गई है।

तिब्बती संस्कृति और धर्म नाभिनाल की तरह परस्पर जुड़े हुए हैं और उनमें अंतर करना मुश्किल है। तिब्बती बौद्ध धर्म की सभी परंपराओं का तिब्बती संस्कृति के संवर्द्धन में अहम योगदान है। यह योगदान शिक्षा के प्रचार और न केवल धर्म के संरक्षण के मामले में, बल्कि तिब्बत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भाषा के संवर्द्धन में भी अहम भूमिका है। तिब्बत में शिक्षा की प्रणाली स्थापित होने से पहले भी समग्र रूप से तिब्बती मठों ने शिक्षण और विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। लगभग हर मठवासी केंद्र का पाठ्यक्रम विशिष्ट परंपराओं के अनुसार मामूली अंतर के साथ लगभग समान है।

तिब्बत में १३०० वर्षों से भी अधिक पुराना साहित्य है। यह सीमा और प्रभाव दोनों के संदर्भ में एशिया की महान साहित्यिक परंपराओं में से एक है। इसके अलावा, तिब्बती बौद्ध परंपरा के भीतर कुछ सबसे आवश्यक धार्मिक दर्शन हैं जो न केवल किताबी माध्यम से बल्कि गुरु-शिष्य परंपरा से मौखिक रूप में चले आ रहे हैं। तिब्बती दार्शनिक दृष्टिकोण ने शैक्षिक संस्थानों के नियंत्रण में रहने वाले लोगों के धार्मिक और राजनीतिक अधिकार को मजबूत किया है और वे तर्क और दर्शन में अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नतीजतन, तिब्बती मठ राष्ट्रीय पहचान, भाषा, धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं।

हालांकि, सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) ने न केवल तिब्बत के भीतर बल्कि तिब्बत के बाहर भी तिब्बती बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। कई स्थानों पर तिब्बती मठों को ध्वस्त कर दिया गया है या भिक्षुओं और भिक्षुणियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाकर उसे बुरी तरह से सीमित कर दिया गया है।

उदाहरण के लिए, सेरा मठ की मठवासी आबादी ८,००० और १०,००० भिक्षुओं के बीच थी, जिससे यह डेपुंग मठ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ बन गया था। १९५९ में चीनी सेना द्वारा ल्हासा पर पूरी तरह से कब्जा करने के दौरान सेरा मठ पर बमबारी की गई और मठों के आवासीय क्वार्टर पूरी तरह से नष्ट हो गए। वर्तमान में, चीनी अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के कारण सेरा मठ में केवल ५०० भिक्षुओं की आबादी रह गई है।

पुरस्कार विजेता पत्रकार बारबरा डेमिक ने अपनी किताब, 'ईट द बुद्धाः लाइफ एंड डेथ इन अ तिब्बतन टाउन' में उल्लेख किया है कि वर्तमान में चीनी कब्जे वाले तिब्बत में कोई भी अठारह वर्ष से कम उम्र का भिक्षु नहीं बन सकता है और सभी भिक्षुओं को सीसीपी के प्रचार निर्देश व्याख्यान गुजरना पड़ता है। यह पूरी तरह से प्राचीन तिब्बती परंपराओं का उल्लंघन है।

चीनी सरकार द्वारा किया जा रहा यह निरंतर संशोधन तिब्बतियों के दिलो- दिमाग में जमे धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान को उत्पीड़न और यातना के माध्यम से बदलने के लिए किया जा रहा है। पूरे तिब्बत में मठों की आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास बढ़ रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म सहित विभिन्न धर्मों (झिंझियांग क्षेत्र में इस्लाम जैसे अन्य धर्मों को भी गहराई से प्रभावित किया गया है) के खिलाफ ये सभी कठोर नीतिगत बदलाव शी जिनपिंग के बढ़ते दमन और तिब्बत और पूरे चीन में लाखों आस्थावानों की धार्मिक भावनाओं के प्रति उनकी उदासीनता को प्रदर्शित करते हैं।

१२ अगस्त २०२१ को एक असंतुष्ट विद्वान हू ज़िमो (छ नाम) द्वारा लिखित 'चाइना : फर्स्ट सीसीपी नेशनल कांफ्रेंस ऑन रिलिजियस हेलड सिंस २०१६ (चीनः २०१६ के बाद से आयोजित धर्म पर पहला सीसीपी राष्ट्रीय सम्मेलन)' शीर्षक वाला शोध आलेख विस्तार से बताता है कि कैसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धर्म पर और अधिक कठोर कार्रवाई की योजना की घोषणा की थी। लेखक ने आगे विस्तार से बताया कि सम्मेलन में सीसीपी के सभी शीर्ष नेताओं ने भाग लिया था और इसी पैमाने पर इन दमनों की योजना बनाई गई थी। उस भाषण में शी ने उन 'समस्याओं' का उल्लेख किया था जो उनके अनुसार अभी भी धार्मिक प्रचार में मौजूद हैं। शी जिनपिंग ने अधिक मार्क्सवाद, इंटरनेट की निगरानी और चीनीकरण के बारे में बताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर 'धार्मिक प्रचार' को रोकने की भी मांग की।

इन योजनाओं को कैसे सामने लाया गया है इसका एक उदाहरण ब्लूड नामक सबसे बड़े सामाजिक नेटवर्क में से एक है, जिसे २०१२ में लॉन्च किया गया था। यह नेटवर्क समलैंगिक समुदाय में चीन में काफी प्रसिद्ध है। लेकिन १२ अप्रैल २०२१ को चेन ताओ द्वारा लिखे एक लेख 'चाइनीज एलजीबीटी सोशल मीडिया ऐप बैन्ड यूजर्स फ्रॉम पोस्टिंग रिलिजियस कंटेंट (चीनी एलजीबीटी सोशल मीडिया ऐप ने उपयोगकर्ताओं को धार्मिक सामग्री पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया)' में विस्तार से बताया गया है कि चीन में समलैंगिकों को इस नेटवर्क पर धार्मिक मामलों पर अपनी राय व्यक्त करने की सख्त मनाही कर दी गई है। हालांकि धार्मिक पोस्ट अभी भी जारी हैं, लेकिन अगर वे चीनी अधिकारियों द्वारा पकड़े जाते हैं तो लेखकों के खाते अवरुद्ध कर दिए जाते हैं।

३ जनवरी २०२१ को सीसीपी के मुखपत्र- द ग्लोबल टाइम्स ने 'ऑब्जर्विंग हिस्टोरिकल कन्वेंशनः द रिइनकार्नेशन ऑफ तिब्बती लिविंग बुद्धा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यूरिस्डिक्शन' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में लेखक ने उल्लेख किया कि जीवित बुद्ध का पुनर्जन्म तिब्बती बौद्ध परंपरा के नेताओं के उत्तराधिकार की समस्या को सुलझाने के लिए है। जनवरी २०१६ में 'स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलिजियस अफेयर्स (धार्मिक मामलों के सरकारी प्रशासन)' ने घोषणा की थी कि सभी पुनर्जन्म वाले लामाओं को सीसीपी द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिए। पुनर्जन्म वाले लामाओं की इस सूची में सभी आधिकारिक 'जीवित बुद्ध' भी शामिल किए गए थे। निर्वासित बुद्ध १४वें दलाई लामा का नाम भी सूची में पाया गया। सीसीपी यह सुनिश्चित करने के लिए बौद्ध धर्म के हर पहलू को अपने नियंत्रण में लाने के लिए काम कर रही है कि केवल उन आध्यात्मिक हस्तियों को ही अनुमति दी जाए, जिनका सरकार द्वारा 'अनुमोदन' किया गया हो।

हाल ही में १४ दिसंबर २०२१ को सोफी रिचर्डसन द्वारा लिखे गए आलेख 'चाइनीज अथॉरिटीज डबल डाउन ऑन तिब्बतन रिइनकार्नेशन (तिब्बती पुनर्जन्म पर चीनी प्राधिकरण का डबल डाउन)' में लेखक ने संकेत दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य अगले दलाई लामा के चयन पर भी पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना है। तिब्बत नीति संस्थान के पूर्व निदेशक थुब्टेन सम्फेल ने लिखा है कि यदि बीजिंग द्वारा अगले दलाई लामा की नियुक्ति सफल हो जाती है, तो यह बिना एक गोली चलाए पूरे बौद्ध हिमालयी क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लेगा।

तिब्बत में शिक्षा और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में तिब्बती मठों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तिब्बती मठों में प्रदान किए गए विद्वानों के प्रशिक्षण ने क्षेत्र की संस्कृति, धर्म और भाषा को बनाए रखा है। मठ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो अंततः परंपरा में विश्वास लाता है और किसी की (लुप्तप्राय) राष्ट्रीयता के विलुप्त होने को रोकने के लिए साधन और क्षमता लाता है। इस बात से कम्युनिस्ट विचारधारा का कड़ा विरोध है। इसलिए तिब्बत में होने वाले अधिकांश आत्मदाह (चीनी उत्पीड़न का विरोध) भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि शी जिनपिंग तिब्बत में पारंपरिक बौद्ध धर्म के खिलाफ हैं और इससे पता चलता है कि क्यों उनकी सेना प्रतिष्ठित बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ रही है।

'डॉ. त्सेरिंग डोल्मा तिब्बत नीति संस्थान में शोध अध्येता हैं। यहां व्यक्त किए गए विचार उनके निजी है और जरुरी नहीं कि वे तिब्बत नीति संस्थान के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। यह लेख मूल रूप से १६ जनवरी २०२२ को ग्लोबल ऑर्डर में प्रकाशित हुआ था।

*****

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Jigmey Tsultrim
Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

जिगमे त्सुलट्रिम
समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः indiatibet7@gmail.com

February, 2022, Years: 43 Issue: 02 Regd No. : RNI 34636-79

फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम और अन्य तिब्बत समर्थक समूह

निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की